दिनांक- 22-मार्च-2023

**प्रेस विज्ञप्ति**

- **रेलटेल को मध्य प्रदेश सरकार से स्टेट डेटा सेंटर (एसडीसी) के विस्तार और आपदा रिकवरी (डीआर) केंद्र की स्थापना के चरण-2 परियोजना के लिए 34.91 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) का ऑर्डर मिला है।**

- **इस परियोजना के पूरा होने के परिणामस्वरुप नागरिक को माउस के क्लिक पर ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन्स से जुड़ी अधिक नागरिक केंद्रित लाभकारी योजनाएं उपलब्ध होंगी और नागरिकों को सेवाएं प्राप्त करने में सुधार आएगा।**

- **मध्य प्रदेश सरकार से इस प्रतिष्ठित परियोजना को हासिल करना घरेलू आईटी क्षेत्र में रेलटेल की महत्वता को दर्शाता है। श्री संजय कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक।**

**********

रेल मंत्रालय के तहत सीपीएसयू रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) से स्टेट डेटा सेंटर (एसडीसी) के विस्तार और आपदा रिकवरी (डीआर) केंद्र की स्थापना की परियोजना के चरण -2 के लिए एक ऑर्डर मिला है। कार्य आदेश का मूल्य रुपये 34.91 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) है, जो जीएसटी को शामिल करने के बाद रुपये 41.19 करोड़ (जीएसटी सहित) हो जाता है।
यह ऑर्डर खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया गया है। उक्त परियोजना में मध्य प्रदेश में पांच साल की अवधि के लिए एक आपदा रिकवरी केंद्र की स्थापना के साथ-साथ मध्य प्रदेश में एक स्टेट डेटा सेंटर का ग्रेडेशन, कमीशन और प्रबंधन शामिल है।

स्टेट डेटा सेंटर (एसडीसी) की परिकल्पना राज्य और उसके घटक विभागों/संगठन के ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों की मेजबानी और प्रबंधन के लिए 'साझा, विश्वसनीय और सुरक्षित बुनियादी ढांचा सेवा केंद्र' के रूप में की गई है। यह राज्य के केंद्रीय भंडार, सुरक्षित डेटा संग्रहण, सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी, नागरिक सूचना/सेवा पोर्टल, राज्य इंट्रानेट पोर्टल, आपदा रिकवरी, दूरस्थ प्रबंधन और सेवा एकीकरण जैसी कई कार्यक्षमताएं प्रदान करेगा। एसडीसी जी 2 जी, जी 2 सी और जी 2 बी सेवाओं के सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल वितरण की सुविधा प्रदान करेगा जिससे अंतिम उपयोगकर्ता संतुष्टि में सुधार होगा। कृत्रिम अथवा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले को महंगे सेवा व्यवधानों से बचाव के लिए डिज़ास्टर रिकवरी (DR) सेवाओं की आवश्यकता होती है।

इस परियोजना के पूरा होने पर नागरिक को एक माउस क्लिक पर ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन्स से जुड़ी अधिक नागरिक केंद्रित लाभकारी योजनाएं उपलब्ध होंगी और नागरिकों को सेवाओं के डिलीवरी में सुधार करने में सहयोग मिलेगा। इससे विभिन्न सरकारी पहलों, सार्वजनिक व्यय और योजनाओं में पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार होगा।

**इस बारे में टिप्पणी करते हुए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री संजय कुमार ने कहा, "** रेलटेल अपने ग्राहकों की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में सबसे आगे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार से इस प्रतिष्ठित परियोजना को हासिल करना घरेलू आईटी क्षेत्र में रेलटेल की महत्वता को दर्शाता है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की रीढ़ के रूप में एसडीसी के उभरने के साथ यह परियोजना महत्वपूर्ण हो गई है। हम अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए ऐसी और परियोजनाओं पर नजर रखना जारी रखेंगे। हम अपने ग्राहकों को संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

**रेलटेल के बारे में:**

रेलटेल, रेल मंत्रालय के तहत एक "मिनी रत्न (श्रेणी- I)" केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, देश के सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार बुनियादी ढांचे और आईसीटी समाधान और सेवा प्रदाताओं में से एक है, जिसके पास कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने वाला एक अखिल भारतीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है। ऑप्टिक फाइबर के 61000+ आरकेएम के एक मजबूत विश्वसनीय नेटवर्क के साथ, रेलटेल के पास दो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना मंत्रालय (MeitY) पैनल वाले टियर III डेटा केंद्र भी हैं। अपने अखिल भारतीय उच्च क्षमता नेटवर्क के साथ, रेलटेल विभिन्न क्षेत्रों में पर समाज को ज्ञानार्जित बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है और रेलटेल को दूरसंचार क्षेत्र में भारत सरकार के लिए विभिन्न मिशन-मोड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्य कर रहा है। रेलटेल एमपीएलएस वीपीएन, टेलीप्रेजेंस, लीज्ड लाइन, टॉवर को-लोकेशन, डाटा सेंटर सेवाएं आदि जैसी सेवाओं का एक साथ प्रदान करता है। रेलटेल देश भर के रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक वाई-फाई प्रदान करके रेलवे स्टेशनों को डिजिटल हब में बदलने के लिए भारतीय रेलवे के साथ काम कर रहा है और रेलटेल के रेलवायर वाई-फाई के साथ 6108+ स्टेशन लाइव हैं।

**अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें**:
**sucharita@railtelindia.com**